राकेश कुमार जैन और हरनरेश सिंह गिल के सामने , जे. जे.

राजेश देवी-अपीलार्थी

बनाम

जय प्रकाश-2003 का उत्तरदाता एफ. ए. ओ.-एम. No.51

1 मई, 2019

हिंदू विवाह अधिनियम, **1955**-धारा **13 (1)** (आई. ए.)-हिंदू विवाह (पंजाब) नियम, **1956**-धारा **6,10,11,14**-कथित व्यभिचारी को व्यभिचार के आधार पर तलाक मांगने के लिए सह-प्रत्यर्थी के रूप में आरोपित किया जाना-पत्नी/अपीलकर्ता द्वारा व्यभिचारी जीवन जीने के कारण क्रूरता के आधार पर पति/प्रत्यर्थी के पक्ष में दिया गया तलाक का फरमान-याचिका में व्यभिचारी का नाम है लेकिन सह-प्रत्यर्थी के रूप में आरोपित नहीं किया गया-**2003** में पत्नी द्वारा दायर अपील-**2013** में पति की मृत्यु हो गई-अपील लंबित रहने के दौरान पति की मृत्यु के कारण रखरखाव के सवाल पर विवादित-आयोजित, अपील विचारणीय है क्योंकि उसके जीवनकाल के दौरान उसके पक्ष में पारित तलाक की डिक्री उसे निर्धारित करती है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रारंभ में, प्रत्यर्थी के वकील ने प्रत्यर्थी-पति की मृत्यु के बाद वर्तमान अपील की स्थिरता के संबंध में इस आधार पर एक मुद्दा उठाया है कि तलाक एक व्यक्तिगत उपाय है जिसे पति की मृत्यु के बाद आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।इस संबंध में, उन्होंने श्रीमती के मामले में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया है। यल्लावा बनाम श्रीमती. शांतव्वा, 1997 (11) एस. सी. सी. 159.(पैरा 7) ने आगे अभिनिर्धारित किया कि

दूसरी ओर, अपीलार्थी के वकील ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान अपील पति की मृत्यु के बाद भी बनाए रखने योग्य है क्योंकि पति द्वारा प्राप्त डिक्री कानूनी रूप से प्रभावी है और अपीलार्थी की पत्नी के रूप में स्थिति निर्धारित करती है और साथ ही डिक्री प्रत्यर्थी द्वारा व्यभिचार के झूठे आधारों पर प्राप्त की गई है जो अपीलार्थी को कलंक से जोड़ती है।इस संबंध में, उन्होंने आर. लक्ष्मी बनाम के. सरस्वती अम्मल, 1996 (6) एस. सी. सी. 371 के मामले में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है।उन्होंने बलविंदर कौर बनाम गुरमुख सिंह, 2007 (2) पी. एल. आर. 22 के मामले में दिए गए इस अदालत के फैसले का भी उल्लेख किया है। (पैरा 8)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस प्रकार यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या पति या पत्नी के आग्रह पर, उसके खिलाफ पारित तलाक की डिक्री को चुनौती देने वाली अपील, तब भी कायम रखने योग्य है जब अपील के लंबित रहने के दौरान दूसरे पति या पत्नी की मृत्यु हो जाती है।

(पैरा 9) ने आगे अभिनिर्धारित किया कि इस संबंध में विधि का आर. लक्ष्मी के मामले (ऊपर) में उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटारा किया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भले ही पति की मृत्यु हो गई हो, फिर भी उसके द्वारा प्राप्त डिक्री विधि में प्रभावी है और पत्नी के रूप में अपीलार्थी की स्थिति निर्धारित करती है।एक पत्नी के रूप में उसकी स्थिति निर्धारित करने के अलावा, यह उसके मृत पति की संपत्तियों में उसके अधिकारों को भी निर्धारित करता है, जो उसे अपने पति की मृत्यु के बाद भी तलाक की कार्यवाही को लड़ने का पर्याप्त अधिकार और अधिकार देता है।इस न्यायालय द्वारा बलविंदर कौर के मामले (ऊपर) में प्रत्यर्थी द्वारा श्रीमती के मामले में दिए गए फैसले को संदर्भित करने के बाद इसी तरह का विचार रखा गया है। यल्लावा का मामला (ऊपर)।

(पैरा 10) ने आगे अभिनिर्धारित किया कि इस प्रकार, हमारी यह सुविचारित राय है कि वर्तमान अपील की विचाराधीनता के दौरान पति की मृत्यु के बाद भी वर्तमान अपील विचारणीय है क्योंकि व्यभिचार के आधार पर उसके जीवनकाल के दौरान उसके पक्ष में पारित तलाक की डिक्री प्रतिवादी (मृत पति) की पत्नी के रूप में उसकी स्थिति का निर्धारण करेगी और उसकी पत्नी के रूप में उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के उसके अधिकार को भी प्रभावित करेगी।(पैरा 11) ने आगे अभिनिर्धारित किया कि इस प्रकार, विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या व्यभिचार के आधार पर तलाक की मांग के लिए दायर याचिका सह-प्रतिवादी के रूप में व्यभिचारी को आरोपित किए बिना दायर की गई है, हालांकि उस व्यक्ति के बारे में जानकारी होने के बावजूद जिसके साथ पति या पत्नी यौन संबंध बना रहे हैं और याचिका में भी इसका उल्लेख किया गया है, नियमों के नियम 10 को ध्यान में रखते हुए बनाए रखा जा सकता है?(पैरा 15) ने आगे कहा कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए व्यभिचार की परिभाषा को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा, जिसे लिया गया है।

संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड शब्दकोश से और इसका अर्थ है "स्वैच्छिक यौन संबंध।

एक विवाहित व्यक्ति और एक ऐसे व्यक्ति के बीच संभोग जो उनका नहीं है

पति "।अधिनियम की धारा 14 और 21 उच्च न्यायालय को अधिकार देती है -

नियम बनाए गए हैं और उनके अनुसरण में नियम बनाए गए हैं जिनमें नियम 6,10,11 और 14 प्रासंगिक हैं, जिन्हें निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"6. व्यभिचार के पूर्ण तथ्य दिए जाने चाहिए।--

6.राजेश देवी बनाम जय प्रकाश के लिए किसी भी याचिका में

तलाक याचिकाकर्ता को प्रतिवादीगण या प्रतिवादियों द्वारा कथित रूप से किए गए व्यभिचार के कृत्यों का विवरण देना

आवश्यक होगा, जैसा भी मामला हो।

XXXXXXXXXX

10. व्यभिचार के आधार पर याचिकाःव्यभिचारी को पार्टी के रूप में शामिल किया जाना।-- व्यभिचार के आधार पर तलाक के लिए पति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर, याचिकाकर्ता कथित व्यभिचारी को सह-प्रतिवादी बनाएगा। तथापि, याचिकाकर्ता को न्यायालय की अनुमति से निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर ऐसा करने से छूट दी जा सकती हैः—

(क) कि प्रतिवादी एक वेश्या का जीवन जी रही है और याचिकाकर्ता किसी विशेष व्यक्ति के बारे में नहीं जानता है जिसके साथ व्यभिचार किया गया है;

(ख) कि कथित व्यभिचारी का नाम याचिकाकर्ता को अज्ञात है, हालाँकि उसने इसका पता लगाने के लिए उचित प्रयास किए हैं;

(ग) कि कथित व्यभिचारी मर चुका है। 11. व्यभिचारियों को दिए जाने वाले अभिवचनों की वास्तविक प्रति।— जहाँ किसी पति पर किसी नामित व्यक्ति के साथ व्यभिचार का आरोप लगाया जाता है, वहाँ ऐसे आरोप वाले अभिवचनों की एक सच्ची प्रति, जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश नहीं देता है, उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसके साथ व्यभिचार किया गया है, एक सूचना के साथ कि ऐसा व्यक्ति, उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर, कारण में हस्तक्षेप करने के लिए अनुमति लेने के लिए आवेदन करने का हकदार है।

XXXXXXXXXX

14. व्यभिचारी को पूरी या आंशिक लागत का भुगतान करना होता है।-- जब भी किसी पति द्वारा प्रस्तुत किसी याचिका में, कथित व्यभिचारी को संवाददाता बनाया गया है और व्यभिचार स्थापित किया गया है, तो न्यायालय सह-प्रतिवादी को कार्यवाही के पूरे या किसी भी हिस्से के खर्च का भुगतान करने का आदेश दे सकता है; बशर्ते कि सह-प्रतिवादी को याचिकाकर्ता के खर्च का भुगतान करने का आदेश नहीं दिया जाएगा-(i) यदि प्रतिवादी, व्यभिचार के समय अपने पति से अलग रह रहा था और एक वेश्या का जीवन जी रहा था, या (ii) यदि सह-प्रतिवादी ने व्यभिचार के समय, यह मानने का कारण नहीं दिया था कि प्रतिवादी एक व्यभिचारी था।

विवाहित महिला।"

(पैरा 16) ने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 13 (1) (आई. ए.) क्रूरता के आधार से संबंधित है लेकिन अधिनियम की धारा 13 (1) (आई.) व्यभिचार के आधार से संबंधित है। वर्तमान मामले में, व्यभिचारी, जिसका विशेष रूप से पैरा संख्या में नाम लिया गया है, को आरोपित किए बिना अपीलार्थी द्वारा व्यभिचारी के कथित कार्य पर प्रत्यर्थी को डिक्री दी गई है। 9 याचिका से। नियमों के नियम 6 में प्रावधान है कि यदि व्यभिचार के आधार पर तलाक के लिए

याचिका दायर की जाती है, तो व्यभिचारी का विवरण जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। नियमों के नियम 10 में प्रावधान है कि याचिकाकर्ता पति या पत्नी पर यह दायित्व है कि वह व्यभिचारी को सह-प्रतिवादी के रूप में शामिल करे, लेकिन तीन अपवादों के लिए जो उसमें दिए गए हैं। नियम 11 में आगे कहा गया है कि अभिवचनों की प्रति उक्त व्यभिचारी को दी जानी है और नियम 14 में आगे कहा गया है कि यदि व्यभिचार स्थापित हो जाता है, तो न्यायालय व्यभिचारी को नियमों में दिए गए दो अपवादों को छोड़कर पूरी राशि का भुगतान करने या कार्यवाही की लागत का कुछ हिस्सा देने का आदेश दे सकता है।

(पैरा 17) ने आगे कहा कि इस प्रकार, उपरोक्त नियमों से, यह स्पष्ट है कि व्यभिचार का आरोप लगाने वाले पति या पत्नी को कथित व्यभिचारी को एक पक्ष के रूप में शामिल करना होगा और सह-प्रतिवादी के रूप में उक्त व्यभिचारी की अनुपस्थिति में, व्यभिचार की याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 18) ने आगे कहा कि हालांकि व्यभिचारी की अनुपस्थिति में, जिसका नाम पैरा नं.9 प्रत्यर्थी-पति द्वारा दायर याचिका में, याचिका स्वयं परिवार न्यायालय के समक्ष बनाए रखने योग्य नहीं थी, लेकिन हम प्रत्यर्थी के नेतृत्व वाले साक्ष्य का भी उल्लेख करेंगे, जिसे परिवार न्यायालय द्वारा गलत तरीके से पढ़ा गया है, जबकि यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अपीलार्थी व्यभिचारी जीवन जी रहा था।

(पैरा 19)

N.S.Shekhawat, अधिवक्ता,

अपीलार्थी के लिए।

प्रत्यर्थी नं. के लिए प्रतिभा यादव, अधिवक्ता। 1.

राकेश कुमार जैन, जे।

(1) अपीलार्थी-पत्नी परिवार न्यायालय द्वारा पारित 20.12.2002 दिनांकित निर्णय और डिक्री के खिलाफ व्यथित है, जिसके द्वारा प्रतिवादी (मृत होने के कारण) के साथ उसकी शादी क्रूरता के आधार पर भंग कर दी गई थी।

राजेश देवी बनाम जय प्रकाश

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी के साथ अपीलार्थी का विवाह गोकलगढ़ गाँव, तहसील और जिला रेवाड़ी में हिंदू संस्कारों और समारोहों के अनुसार 14.02.1982 पर किया गया था। विवाह के समय, प्रत्यर्थी एक विधुर था क्योंकि उसकी पहली पत्नी, रामावती की मृत्यु हो गई थी और उक्त विवाह से उसका एक बेटा हुआ, जिसका नाम रविंदर कुमार था, जबकि अपीलार्थी एक सहायक था। प्रत्यर्थी-पति द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि दो बेटे, दीपेंद्र और योगेंद्र, उक्त विवाह से पैदा हुए थे और जब वह अहमदाबाद में गुजरात पुलिस में सेवा में थे, तो अपीलार्थी ने अपने गाँव

गोकलगढ़ के किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध विकसित किए। यह भी दलील दी गई कि अपीलार्थी ने खुद को एक बुरी महिला बताकर अपने पत्रों में व्यभिचार के कृत्य को स्वीकार किया था। अभिवचनों में आगे यह कहा गया कि अपीलार्थी उसे नपुंसक (हिजरा) कहता था और घर का काम करने से इनकार कर देता था। यह स्पष्ट रूप से पैरा नं.9 याचिका में कहा गया है कि अगस्त 1995 के महीने में, जब वह निमोथ गांव में थी, तो उसके दो दोस्त स्कूटर पर उसके घर आए और उसकी उपस्थिति में, उन्होंने एक बंद कमरे में अपीलार्थी से बात की और मास्टर मुकेश ने उसकी उपस्थिति में उसे चूमा। अपीलार्थी और उसके दोस्त ने उसके घर में शराब पी और उसकी उपस्थिति में यौन क्रिया की, इसलिए यह क्रूरता का कार्य है। यह आगे बताया गया है कि वह सेवा में था और अगस्त 1995 से 15.10.1997 तक अपने गाँव नहीं आया था और इस अवधि के दौरान, अपीलार्थी को 5 से 6 महीने की गर्भावस्था थी और रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल में 18.10.1997 पर उसका गर्भपात कर दिया गया था। इस प्रकार, प्रत्यर्थी-पति ने व्यभिचारी जीवन जीने के कारण अपीलार्थी द्वारा की गई क्रूरता के आधार पर 20.10.1997 पर याचिका दायर करके तलाक की डिक्री की मांग की है। (3) प्रत्यर्थी-पति द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का अपीलार्थी ने अपने लिखित बयान में खंडन किया, बल्कि उसने आरोप लगाया है कि उसका पति शुरू से ही शराबी था और उसे और बच्चों को बनाए रखने के बजाय अपनी सारी आय उसकी बुरी आदतों को आगे बढ़ाने के लिए खर्च करता था और जब भी वह उसकी बुरी आदतों के बारे में शिकायत करती थी तो उसे पीटता था ।

(4) पक्षों की दलीलों पर, दो मुद्दों को तैयार किया गया था

परिवार न्यायालय 27.03.1998 पर, अर्थात्, "(1) क्या याचिकाकर्ता है

क्रूरता के आधार पर प्रत्यर्थी से तलाक लेने का हकदार

व्यभिचार के रूप में?ओ. पी. पी. "और" (2) राहत "।

(5) प्रत्यर्थी-पति ने खुद को पीडब्लू1, उनके भाई जसवंत सिंह को पीडब्लू2, अजीत सिंह, कलावती अस्पताल के रिकॉर्ड कीपर को पीडब्लू3 और सरपंच रामेश्वर को पीडब्लू4 के रूप में जांच की थी, जबकि अपीलार्थी ने उमा 894 के रिकॉर्ड कीपर चंद्र प्रकाश की जांच की थी।

भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रेवाड़ी आर. डब्ल्यू. 1 के रूप में, खुद आर. डब्ल्यू. 2 के रूप में, राज कुमार आर. डब्ल्यू. 3 के रूप में और राम अवतार आर. डब्ल्यू. 4 के रूप में।निचली अदालत ने, प्रतिवादी के नेतृत्व में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के बाद, यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता एक व्यभिचारी जीवन जी रहा था जो क्रूरता का गठन करता है और इसलिए, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 13 (1) (आई. ए.) के तहत तलाक की डिक्री प्रदान की।

(6) अपीलार्थी-पत्नी ने वर्तमान अपील के माध्यम से उक्त डिक्री को चुनौती दी है, जिसे 07.10.2003 पर स्वीकार

किया गया था। इसके बाद, यह रिकॉर्ड में आया कि प्रतिवादी-पति की मृत्यु 18.11.2013 पर हुई थी और उनकी मृत्यु से पहले, उन्होंने अपनी पिछली पत्नी के बेटे रविंदर कुमार के पक्ष में अपनी संपत्ति को वसीयत करते हुए 25.03.2008 दिनांकित एक पंजीकृत वसीयत को निष्पादित किया था। अपीलार्थी ने प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए आदेश 22 नियम 4 के तहत 2015 के सीएम No.21703-CII वाला एक आवेदन भी दायर किया था, जिसे सीपीसी की धारा 151 के साथ पढ़ा गया था। उक्त आवेदन को 23.07.2016 पर निम्नलिखित आदेश के साथ अनुमति दी गई थीः-

"यह आदेश 22 नियम 4 के तहत दायर एक आवेदन है।

प्रतिवादी-पति के कानूनी प्रतिनिधि को शामिल करने के लिए धारा 151 सी. पी. सी. के साथ।

प्रतिवादीगण No.ii और III कोई और नहीं बल्कि अपीलार्थी की संतानें हैं जो मृतक-प्रतिवादीगण, जय प्रकाश के साथ अपीलार्थी के विवाह से पैदा हुई हैं। हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, प्रत्यर्थी No.ii और III केवल प्रारूप पक्ष हैं।प्रतिवादी आई-जय प्रकाश, मृतक के पहले विवाह से पैदा हुआ बेटा-जय प्रकाश, मृतक-जय प्रकाश के पक्ष में दिए गए तलाक के फरमान को चुनौती देने वाली राजेश देवी द्वारा दायर वर्तमान अपील में एक आवश्यक पक्षकार पाया गया है। इसलिए, आवेदन की अनुमति है। पक्षों के संशोधित ज्ञापन को रिकॉर्ड में लिया जाता है।

श्री जतिंदर के. सेहरावत, अधिवक्ता ने वकालतनामा दायर किया

प्रतिवादीगण No.ii और iii के लिए।"

(7) शुरुआत में, प्रत्यर्थी के वकील ने प्रत्यर्थी-पति की मृत्यु के बाद वर्तमान अपील की स्थिरता के बारे में इस आधार पर एक मुद्दा उठाया है कि तलाक एक व्यक्तिगत उपाय है जिसे पति की मृत्यु के बाद आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में, उन्होंने राजेश देवी बनाम जय प्रकाश में दिए गए उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

श्रीमती का मामला। यल्लावा बनाम श्रीमती। शांतव्व 1.

(8) दूसरी ओर, अपीलार्थी के वकील ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान अपील पति की मृत्यु के बाद भी बनाए रखने योग्य है क्योंकि पति द्वारा प्राप्त डिक्री कानूनी रूप से प्रभावी है और अपीलार्थी की पत्नी के रूप में स्थिति निर्धारित करती है और डिक्री भी प्रत्यर्थी द्वारा व्यभिचार के झूठे आधार पर प्राप्त की गई है जो अपीलार्थी को कलंक लगाती है। इस संबंध में, उन्होंने आर. लक्ष्मी बनाम के. सरस्वती अम्मल 2 के मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। उन्होंने बलविंदर कौर बनाम गुरमुख के मामले में दिए गए इस अदालत के फैसले का भी उल्लेख किया है।

सिंह 3.

(9) इस प्रकार, सवाल यह उठता है कि क्या पति या पत्नी के कहने पर, उसके खिलाफ पारित तलाक की डिक्री को चुनौती देने वाली अपील विचारणीय है, भले ही अपील के लंबित रहने के दौरान दूसरे पति या पत्नी की मृत्यु हो जाए?

(10) आर. लक्ष्मी के मामले (उपरोक्त) में उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में कानून का निपटारा किया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भले ही पति की मृत्यु हो गई हो, फिर भी उसके द्वारा प्राप्त डिक्री कानून में प्रभावी है और पत्नी के रूप में अपीलार्थी की स्थिति निर्धारित करती है।एक पत्नी के रूप में उसकी स्थिति निर्धारित करने के अलावा, यह उसके मृत पति की संपत्तियों में उसके अधिकारों को भी निर्धारित करता है, जो उसे अपने पति की मृत्यु के बाद भी तलाक की कार्यवाही को लड़ने का पर्याप्त अधिकार और अधिकार देता है। इस न्यायालय द्वारा बलविंदर कौर के मामले (ऊपर) में प्रत्यर्थी द्वारा श्रीमती के मामले में दिए गए फैसले को संदर्भित करने के बाद इसी तरह का विचार रखा गया है। यल्लावा का मामला (ऊपर)।

(11) इस प्रकार, हमारी यह सुविचारित राय है कि वर्तमान अपील वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान पति की मृत्यु के बाद भी विचारणीय है क्योंकि व्यभिचार के आधार पर उसके जीवनकाल के दौरान उसके पक्ष में पारित तलाक की डिक्री प्रतिवादी (मृत पति) की पत्नी के रूप में उसकी स्थिति निर्धारित करेगी और उसकी पत्नी के रूप में उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के उसके अधिकार को भी प्रभावित करेगी।

(12) गुण-दोष पर, अपीलार्थी के वकील ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी अपीलार्थी द्वारा व्यभिचार के कार्य के आधार पर क्रूरता के कथित कार्य को साबित करने में विफल रहा है। हालाँकि, परिवार न्यायालय द्वारा कथित रूप से गलत तरीके से पढ़े गए साक्ष्य का उल्लेख करने से पहले, उनके पास 1 1997 (11) एससीसी 159 है।

2 1996(6) एससीसी 371

3 2007(2) पी. एल. आर. 22 896

प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी ने अपनी याचिका में उक्त व्यभिचारी को सह-प्रत्यर्थी के रूप में शामिल नहीं किया था, हालांकि उसने विशेष रूप से पैरा संख्या में उसका नाम लिया है। 9 उनकी याचिका, जो हिंदू विवाह (पंजाब) नियम, 1956 (इसके बाद के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के विपरीत है

“नियम ") और इस संबंध में, उन्होंने विशेष रूप से नियम 10 का उल्लेख किया है

नियम हैं। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि पैरा नं.9 तलाक याचिका में, अपीलार्थी ने निम्नानुसार प्रतिवाद किया हैः-

“9. कि अगस्त 1995 के महीने में जब वह

गाँव निमोथ प्रतिवादी के दो दोस्त एक नाम XXXXX गाँव गोकलगढ़ स्कूटर पर याचिकाकर्ता के घर आते हैं और याचिकाकर्ता की उपस्थिति में वे एक बंद कमरे में प्रतिवादी से बात करते हैं और मास्टर मुकेश उसकी उपस्थिति में उसे चूमता है और प्रतिवादी उसके दोस्त ने घर में शराब का इस्तेमाल किया और याचिकाकर्ता के घर में यौन आनंद लिया।

इसलिए यह याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता है।"

(13) अपीलार्थी के विद्वान वकील ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि कथित व्यभिचारी को तलाक याचिका में सह-प्रत्यर्थी के रूप में शामिल करने में प्रत्यर्थी की ओर से विफलता को देखते हुए, व्यभिचार की याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती है और इस संबंध में, उन्होंने डॉ. अशोक कुमार के मामले में दिए गए इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

अग्रवाल बनाम श्रीमती। अंजू राजे 4.

(14) प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने उपरोक्त संबंध में अपीलार्थी के वकील के तर्क का विरोध करने के लिए किसी अन्य नियम या कानून के प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया है और न ही उसके समर्थन में किसी निर्णय का उल्लेख किया है।

(15) इस प्रकार, विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या व्यभिचार के आधार पर तलाक की मांग करने के लिए दायर की गई याचिका, जिसमें व्यभिचारी को सह-प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया है, हालांकि उस व्यक्ति के बारे में जानकारी है जिसके साथ पति या पत्नी यौन संबंध बना रहे हैं और याचिका में भी इसका उल्लेख किया गया है, नियम के नियम 10 को ध्यान में रखते हुए बनाए रखा जा सकता है?

(16) इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, व्यभिचार की परिभाषा का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जिसे

संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड शब्दकोश और इसका अर्थ है "एक विवाहित व्यक्ति और एक ऐसे व्यक्ति के बीच स्वैच्छिक यौन संभोग जो उनका जीवनसाथी नहीं है।"

अधिनियम की धारा 14 और 21 उच्च न्यायालय को नियम बनाने का अधिकार देती है और उसके अनुसरण में नियम बनाए गए हैं जिसमें 4 2011 (6) आर. सी. आर. (आपराधिक) 1639 राजेश देवी बनाम जय प्रकाश

नियम 6,10,11 और 14 प्रासंगिक हैं, जिन्हें निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"6. व्यभिचार के पूर्ण तथ्य दिए जाने चाहिए।--6.किसी भी याचिका में

तलाक के लिए याचिकाकर्ता से, यथास्थिति, प्रत्यर्थी या प्रतिवादीगण द्वारा किए गए कथित व्यभिचार के कृत्यों के बारे में जितना हो सके, विवरण देने की आवश्यकता होगी।

XXXXXXXXXX

10. व्यभिचार के आधार पर याचिकाःव्यभिचारी होना

पार्टी के रूप में शामिल।-- व्यभिचार के आधार पर तलाक के लिए पति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर, याचिकाकर्ता कथित व्यभिचारी को सह-प्रतिवादी बनाएगा।तथापि, याचिकाकर्ता को न्यायालय की अनुमति से निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर ऐसा करने से छूट दी जा सकती हैः—

(क) कि प्रतिवादी एक वेश्या का जीवन जी रहा है और याचिकाकर्ता किसी विशेष व्यक्ति के बारे में नहीं जानता है जिसके साथ व्यभिचार किया गया है;

(ख) कि कथित व्यभिचारी का नाम याचिकाकर्ता को अज्ञात है, हालाँकि उसने इसका पता लगाने के लिए उचित प्रयास किए हैं;

(ग) कि कथित व्यभिचारी मर चुका है।

11. व्यभिचारियों को दिए जाने वाले अभिवचनों की वास्तविक प्रति।--

जहाँ किसी पति पर किसी नामित व्यक्ति के साथ व्यभिचार का आरोप लगाया जाता है, वहाँ ऐसे आरोप वाले अभिवचनों की एक सच्ची प्रति, जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश नहीं देता है, उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसके साथ व्यभिचार किया गया है, एक सूचना के साथ कि ऐसा व्यक्ति, उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर, कारण में हस्तक्षेप करने के लिए अनुमति के लिए आवेदन करने का हकदार है।

XXXXXXXXXX

14. व्यभिचारी को पूरी या आंशिक लागत का भुगतान करना होता है।-- जब भी

पति द्वारा प्रस्तुत किसी भी याचिका में, कथित व्यभिचारी को संवाददाता बना दिया गया है और व्यभिचार स्थापित हो गया है, न्यायालय सह-प्रतिवादी को कार्यवाही की लागत का पूरा या किसी भी हिस्से का भुगतान करने का आदेश दे सकता है; बशर्ते कि सह-प्रतिवादी को याचिकाकर्ता के खर्च का भुगतान करने का आदेश नहीं दिया जाएगा-(i) यदि प्रतिवादी 898 के समय था

व्यभिचार जो अपने पति से अलग रह रही थी और एक वेश्या का जीवन जी रही थी , या (ii) यदि सह-प्रत्यर्थी ने व्यभिचार के समय, प्रत्यर्थी पर विश्वास करने का कारण नहीं था

एक विवाहित महिला ।"

(17) अधिनियम की धारा 13 (1) (आई. ए.) क्रूरता के आधार से संबंधित है लेकिन अधिनियम की धारा 13 (1) (आई.) व्यभिचार के आधार से संबंधित है। वर्तमान मामले में, व्यभिचारी, जिसका विशेष रूप से पैरा संख्या में नाम लिया गया है, को आरोपित किए बिना अपीलार्थी द्वारा व्यभिचारी के कथित कार्य पर प्रत्यर्थी को डिक्री दी गई है। 9 याचिका से। नियमों के नियम 6 में प्रावधान है कि यदि व्यभिचार के आधार पर तलाक के लिए याचिका दायर की जाती है, तो व्यभिचारी का विवरण जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए।नियमों के नियम 10 में प्रावधान है कि याचिकाकर्ता पति या पत्नी पर यह दायित्व है कि वह व्यभिचारी को सह-प्रतिवादी के रूप में शामिल करे, लेकिन तीन अपवादों के लिए जो उसमें दिए गए हैं। नियम 11 में आगे कहा गया है कि अभिवचनों की प्रति उक्त व्यभिचारी को दी जानी है और नियम 14 में आगे कहा गया है कि यदि व्यभिचार स्थापित हो जाता है, तो न्यायालय व्यभिचारी को नियमों में दिए गए दो अपवादों को छोड़कर पूरी राशि का भुगतान करने या कार्यवाही की लागत का कुछ हिस्सा देने का आदेश दे सकता है।

(18) इस प्रकार, उपरोक्त नियमों से, यह स्पष्ट है कि व्यभिचार का आरोप लगाने वाले पति या पत्नी को कथित व्यभिचारी को एक पक्ष के रूप में शामिल करना होगा और सह-प्रतिवादी के रूप में उक्त व्यभिचारी की अनुपस्थिति में, व्यभिचार की याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(19) हालाँकि व्यभिचारी की अनुपस्थिति में, जिसका नाम पैरा नं.9 प्रत्यर्थी-पति द्वारा दायर याचिका में, याचिका स्वयं परिवार न्यायालय के समक्ष बनाए रखने योग्य नहीं थी, लेकिन हम प्रत्यर्थी के नेतृत्व वाले साक्ष्य का भी उल्लेख करेंगे, जिसे परिवार न्यायालय द्वारा गलत तरीके से पढ़ा गया है, जबकि यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अपीलार्थी व्यभिचारी जीवन जी रहा था।

(20) अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि प्रत्यर्थी ने एक मामला स्थापित किया है कि वर्ष 1985 और 1987 में अपीलार्थी से अपने बच्चों के जन्म के बाद, उसका नसबंदी ऑपरेशन किया गया था और वह गर्भावस्था का कारण बनने में सक्षम नहीं था। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्ष 1992 में, जब वह छुट्टियों में घर आया, तो उसके परिवार के सदस्यों ने उसे बताया कि अपीलार्थी गर्भवती थी और रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल में उसका गर्भपात हुआ था। उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि 1997 में, उन्हें पता चला कि अपीलार्थी ने कुछ दवा खाने के बाद एक और गर्भपात किया था और भ्रूण को चारा कक्ष में एक थैली में रखा था। उसने कथित तौर पर डी. डी. आर. के माध्यम से पुलिस को मामले की सूचना दी थी, लेकिन गर्भपात को अपराध नहीं पाए जाने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई।

(21) अपीलार्थी के वकील ने प्रस्तुत किया है कि प्रत्यर्थी ने अपनी याचिका में वर्ष 1987 में नसबंदी ऑपरेशन के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था और इसलिए, उनके नेतृत्व में इस संबंध में साक्षय को परिवार न्यायालय द्वारा विचार में नहीं लिया जाना चाहिए था।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि परिवार न्यायालय ने अपीलार्थी को गवाह के रूप में पेश होने के दौरान दिए गए सुझाव पर भरोसा किया था, हालांकि यह राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड

पीठ द्वारा श्रीमती के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है। मधु बनाम मुकेश नारयार और अन्य 5 कि व्यभिचार के आरोप को स्थापित करने की आवश्यकता है, हालांकि प्रत्यक्ष साक्ष्य से नहीं, बल्कि निर्विवाद चरित्र के साक्ष्य से, विशेष रूप से जब उक्त आरोप शादी और दो बच्चों के जन्म के इतने वर्षों के बाद लगाया गया है।उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी और उसके भाई का मौखिक साक्षय अपीलार्थी की ओर से व्यभिचार के कथित कार्य को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है और दस्तावेजी साक्षय, कलावती अस्पताल का रिकॉर्ड, यह दिखाने के लिए विश्वास को प्रेरित नहीं करता है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त अस्पताल से लिया गया उपचार गर्भपात के उद्देश्य से था। उन्होंने आगे कहा है कि हालांकि अपीलकर्ता ने अपने बेटों दीपेंद्र और योगेंद्र के जन्म का उल्लेख वर्ष 1988 और 1989 में किया है, लेकिन वे वास्तव में वर्ष 1985 और 1987 में पैदा हुए थे और उनकी जन्म तिथि 1988 और 1989 के रूप में उल्लिखित की गई थी ताकि उन्हें स्कूल रिकॉर्ड में छोटा दिखाया जा सके क्योंकि वे उस समय अधिक उम्र के हो गए थे। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी मामले में, अपीलार्थी ने अपनी याचिका में इस बात से इनकार नहीं किया है कि वह दोनों बच्चों का पिता है और दोनों बच्चों के जन्म के बाद व्यभिचार का आरोप लगाया है जब उसे पता चला कि अपीलार्थी ने वर्ष 1992 में कलावती अस्पताल में एक बच्चे का गर्भपात किया था। उसके द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी ने अपने किसी भी पत्र Ex.PX और Ex.PY में व्यभिचार के कार्य को स्वीकार नहीं किया है, बल्कि उसने केवल यह उल्लेख किया है कि उसने कुछ पाप किया है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि उसने व्यभिचार किया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि परिवार न्यायालय ने एक निष्कर्ष दर्ज करने में एक त्रुटि की है कि प्रतिवादी के लिए व्यभिचारी को फंसाना आवश्यक नहीं है क्योंकि उसके लिए व्यभिचारी की पहचान जानना संभव नहीं था क्योंकि वह गुजरात राज्य में सेवारत था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह निष्कर्ष पैरा नं.9 उस याचिका में जिसमें उसने विशेष रूप से उस व्यक्ति का नाम लिया है जिसने अपनी उपस्थिति में अपने घर में अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाए थे।

(22) दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के वकील ने 5 2007 (2) जे प्रस्तुत किया हैःआर 715 900

कि कलावती अस्पताल के दस्तावेजी साक्ष्य (Ex.PW3/A और Ex.PW3/B), अपीलार्थी द्वारा लिखे गए पत्र (Ex.PX और Ex.PY) और प्रतिवादी के गवाहों के नेतृत्व में अन्य मौखिक साक्ष्य यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी व्यभिचार का जीवन जी रहा था।

(23) पक्षकारों के विद्वान वकील को सुनने और इस संबंध में उपलब्ध रिकॉर्ड को देखने के बाद, हमारी राय है कि नीचे दिए गए न्यायालय ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य की सराहना में गलती की है क्योंकि Ex.PW3/A और Ex.PW3/B यह नहीं दर्शाते हैं कि अपीलार्थी ने गर्भपात के उद्देश्य से कलावती अस्पताल में उपचार लिया था और विशेष रूप से, दस्तावेज़ Ex.PW3/B का उल्लेख इस तरह से किया गया है जैसे कि अपीलार्थी महिला के बजाय पुरुष है क्योंकि

उक्त दस्तावेज़ की पहली पंक्ति में लिखा है कि "मैं अपनी औरत की सफाई"

अपनी मरजी से करा रहा हू "।इसी तरह, अभिलेख पर उपलब्ध पत्र, विशेष रूप से Ex.PX और Ex.PY, अपीलार्थी की ओर से किसी व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखने की स्वीकारोक्ति को बिल्कुल नहीं दर्शाते हैं, बजाय इसके कि उसके पति को व्यभिचार के आरोप को साबित करना है।यह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है कि अपीलार्थी ने घर पर गर्भपात के बाद भ्रूण को छुपाया था क्योंकि अपीलार्थी द्वारा गर्भावस्था की समाप्ति के संबंध में प्रतिवादी द्वारा अपने परिवार के सदस्यों में से एक भी महिला की जांच नहीं की गई थी, जो सबसे अच्छा गवाह हो सकता था। अपीलार्थी ने अपने मित्र के बयान पर भरोसा किया है जो गुजरात पुलिस में उसके साथ था और जिसका अपीलार्थी के परिवार से कोई संबंध नहीं है और इस प्रकार, उसके साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

(24) उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी की ओर से व्यभिचार के कार्य को ठोस और विश्वसनीय साक्षय का नेतृत्व करके साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है और उसके द्वारा दायर याचिका भी, उस व्यक्ति के बारे में पूरी तरह से अच्छी तरह से जानते हुए जिसके साथ अपीलार्थी व्यभिचार का कथित जीवन जी रहा था, लेकिन उसे सह-प्रतिवादी के रूप में शामिल किए बिना, नियमों के नियम 10 की दृष्टि से बनाए रखने योग्य नहीं था।(25) इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील को मेधावी होने की अनुमति दी जाती है और न्यायालय द्वारा नीचे दिए गए निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया जाता है, हालांकि लागत के रूप में किसी भी आदेश के बिना।

सुमती जुंद

अस्वीकरणीय :- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णयवादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यानयन के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त रहेगा।

अंजू बाला रहेजा

अनुवादक